Sharp decline in bank loans to infrastructure sector

Vatsala Kamat
feedback@livemint.com

Data from the Reserve Bank of India (RBI) on bank lending to the infrastructure sector shows a sharp contraction over the last two years. This is at a time when the government is going all out to create fresh capacity in infrastructure, be it roads, railways, telecom or irrigation.

From 12.8% year-on-year in January 2014, growth rate in bank loans to the sector as a whole has fallen steadily. By 2015, the growth rate was trickling down to single digits. And, since April, loans to the sector as a whole started contracting.

The biggest contraction was seen in the power sector (-10.4%), followed by telecom (-6.3%). The fact that there is surplus thermal capacity with plants operating at around 60-65% capacity utilization is a reason why even new power generation projects are not on the cards. If at all, renewables is the new buzzword in the power sector. Meanwhile, transmission and distribution projects are being awarded by the government, but these are less capital-intensive.

Roads remain the only appealing sector for bank lending. But here too, the growth rate became marginally negative last November after topping the charts two years ago.

This is certainly not good news. Budgetary support for capital expenditure too hasn't seen much growth this fiscal year.

However, more recently, banks have been saddled with stressed assets in the infrastructure segment, which has perhaps killed their appetite for further lending.

The infrastructure sector is riddled with problems from land acquisition to project delays and cost overruns. Economic viability over the life of these projects is also hard to assess with various risks that crop up.

A white paper released by Crisil Ltd and Assocham in November estimates Rs43 trillion is needed over the next five years to fund the country's ambitious infrastructure plans. Given the issues of asset-liability mismatches and group exposure regulations of RBI, banks may not be able to meet the needs of the infrastructure sector in the near term.

Choked path

Lending by banks across the infrastructure arena has been losing steam over the past couple of years.

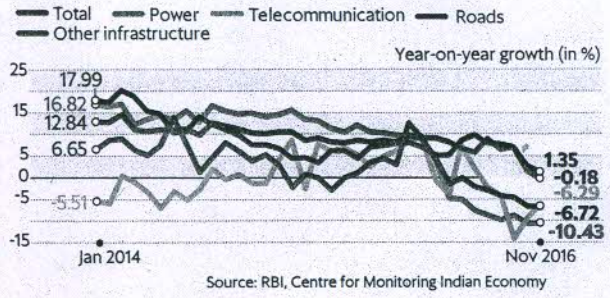

Source: RBI, Centre for Monitoring Indian Economy

AJAY NEGI/MINT

Naya India 19 January, 2017

साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ी

2015 में यह आंकड़ा 3704 रहा था लेकिन 2016 में यह बढ़कर 3973 हो गया।

नई दिल्ली ■ वार्ता

तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर कदम बढ़ा रहे देश में साइबर अपराधों के मामलों में भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही। देश में वर्ष 2014 के दौरान प्रति महीने की औसत से साइबर अपराध के 3723 मामले दर्ज हुए थे और वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 3704 रहा था लेकिन गत साल यह बढ़कर 3973 हो गया। 'सिक्योरिंग द कैशलेस इकोनॉमी' विषय पर उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आज यहां आयोजित वर्कशॉप में प्राइसवाटरहाउस कूपर्स और उद्योग संगठन के संयुक्त अध्ययन में बताया गया कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने अक्टूबर 2016 तक साइबर अपराध के कुल 39,730 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 44,679 और वर्ष 2015 में 49,455 रहा था। साइबर अपराध के मामलों की पहचान और इन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई में होने

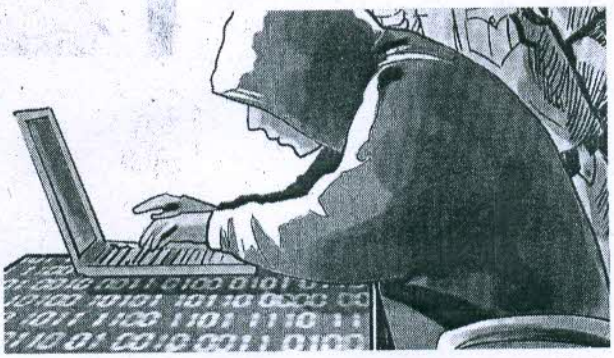

वाली देर से अमेरिका जैसे विकसित बाजारों की अपेक्षा भारत जैसे उभरते बाजारों में साइबर हमलों को बढ़ावा मिलता है। नोटबंदी ने ई-वॉलेट सेवा के लिए विकास के द्वार खोल दिये हैं । मोबाइल वॉलेट सेवा के कारण ऐप डाउनलोन में खासी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों , अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से शहरी आबादी के बीच ऑनलाइन लेनदेन बहुत प्रचलित हो गया है। इसी कारण मोबाइल वॉलेट ऐप डाउनलोड में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वॉलेट रिचार्ज में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल ने ई-कामर्स, एम -कॉमर्स और ऐप आधारित अन्य सेवाओं को बढ़ावा दिया है। ये सभी सेवायें डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती हैं। कैश बैक, बिल भुगतान व्यवस्था, लॉयल्टी प्वाइंट, लॉयल्टी रिवार्ड जैसे वैल्यू ऐडेड सर्विसेज और इस्तेमाल करने में आसानी ने डिजिटल प्लेटफार्म को बढावा दिया है।

देश पर डिजिटल क्रांति से गुजर रहा हो तो डिजिटल प्लेटफार्म के जरिये लेनदेन करने वालों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे साइबर सुरक्षा पर ध्यान दें। गत पांच साल में बैंकिंग प्रणाली में साइबर अपराध की घटनायें बढ़ गई हैं। गत साल अक्टूबर में एटीएम कार्ड हैक स्कैंडल ने भारतीय बैंकों को बुरी तरह हिला कर रख दिया। इस हैंकिंग स्कैंडल से लगभग 32 लाख डेबिट कार्ड प्रभावित हुए। देश में जब बड़ी आबादी डिजिटल दुनिया को अंगीकार कर रही है तो ऐसी स्थिति में साइबर सुरक्षा को सख्त करने की जरुरत है। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए बेंगलरु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस कंप्यूटर विंग) संजय सहाय ने बताया कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपने सुरक्षा मानक, प्रोटोकोल और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि फिशिंग, स्केनिंग, वेबसाइट इंट्रयूजन, वायरस कोड और डिनायल ऑफ सर्विस जैसे साइबर हमले बढेंगे।

नेशनल क्रिटिकल इनफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के महानिदेशक अजीत वाजपेई ने कहा कि नोटबंदी के बाद साइबर हमलों के लिहाज से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र अधिक जोखिम भरे हो गये हैं। उन्होंने कहा कि पहले साइबर अपराध का नुकसान उतना बड़ा नहीं था लेकिन अब इन्होंने विध्वंसक रुप धारण कर लिया है और ये ज्यादा तबाही लाने वाले हो गये हैं। उन्होंने कहा , अखिर एक बैंकिंग ऐप को आपके कैमरा और आपके फोन ऑडियो तक पहुंच क्यों चाहिए।

Dabang Duniya 19 January, 2017

वर्ष 2015 में 49455 मामले दर्ज, औसतन 3704 मामले होते हैं दर्ज

साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ीं

एजेंसी ✡ नई दिल्ली

तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर कदम बढ़ा रहे देश में साइबर अपराधों के मामलों में भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2014 के दौरान प्रति महीने की औसत से साइबर अपराध के 3723 मामले दर्ज हुए थे, और वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 3704 रहा था। लेकिन गत साल (2016) में यह बढ़कर 3973 हो गया। 'सिक्योरिंग द कैशलेस इकोनॉमी' विषय पर उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आयोजित वर्कशॉप में प्राइसवाटरहाउस कूपर्स और उद्योग संगठन के संयुक्त अध्ययन में बताया गया कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने अक्टूबर 2016 तक साइबर अपराध के कुल 39,730 मामले दर्ज किए थे। वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 44,679 और वर्ष 2015 में 49,455 रहा था।

भारत में साइबर हमलों को बढ़ावा

साइबर अपराध के मामलों की पहचान और इन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली देर से अमेरिका जैसे विकसित बाजारों की अपेक्षा भारत जैसे उभरते बाजारों में साइबर हमलों को बढ़ावा मिलता है। नोटबंदी ने ई-वॉलेट सेवा के लिए विकास के द्वार खोल दिए हैं। मोबाइल वॉलेट सेवा के कारण ऐप डाउनलोन में खासी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से शहरी आबादी के बीच ऑनलाइन लेन-देन बहुत प्रचलित हो गया है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र अधिक जोखिम भरे

नेशनल क्रिटिकल इनफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के महानिदेशक अजीत वाजपेयी ने कहा कि नोटबंदी के बाद साइबर हमलों के लिहाज से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र अधिक जोखिम भरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले साइबर अपराध का नुकसान उतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब इन्होंने विध्वंसक रूप धारण कर लिया है और ये ज्यादा तबाही लाने वाले हो गये हैं। उन्होंने कहा,' आखिर एक बैंकिंग ऐप को आपके कैमरा और आपके फोन ऑडियो तक पहुंच क्यों चाहिए। हमें डिजिटल लेनदेन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है।'

32 लाख डेबिट कार्ड प्रभावित : गत पांच साल में बैंकिंग प्रणाली में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। गत साल अक्टूबर में एटीएम कार्ड हैक स्कैंडल ने भारतीय बैंकों को बुरी तरह हिला कर रख दिया। इस हैकिंग स्कैंडल से लगभग 32 लाख डेबिट कार्ड प्रभावित हुए। देश में जब बड़ी आबादी डिजिटल दुनिया को अंगीकार कर रही है तो ऐसी स्थिति में साइबर सुरक्षा को सख्त करने की जरूरत है। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस कंप्यूटर विंग) संजय सहाय ने बताया कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपने सुरक्षा मानक, प्रोटोकोल तथा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि फिशिंग, स्कैनिंग, वेबसाइट इंट्र्यूजन, वायरस कोड और डिनायल ऑफ सर्विस जैसे साइबर हमले बढ़ेंगे।

Naiduniya 19 January, 2017

मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग का लीडर बनने की क्षमता : एसोचैम

इंदौर/नई दिल्ली। नप्र/एजेंसी

मध्यप्रदेश फूड प्रोसेसिंग के मामले में लीडर बनकर उभर सकता है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत और टारी की डायरेक्टर क्षमा कौशिक ने शहर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर रिपोर्ट जारी करते हुए यह बात कही।

रावत ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। यहां देश का सबसे ज्यादा 60 फीसदी सोयाबीन की खेती की जाती है। प्रदेश में दालहन का उत्पादन भी 27 फीसदी होता है। यहां देश का 11 फीसदी सरसों का उत्पादन होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में पिछले साल के 6 लाख करोड़ के निवेश में फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित प्रोडक्ड को सिर्फ 3,382 करोड़ रुपए मिले।

समग्र खाद्य सुरक्षा नीति की जरूरत

रावत के मुताबिक मध्यप्रदेश को तिलहन आधारित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। यहां इस इंडस्ट्री के कुल उत्पादन का आधा माल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारत को एक समग्र खाद्य सुरक्षा नीति की जरूरत है। उत्पादन के मामले में भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पांचवे नंबर पर है। 2014-15 के दौरान जीडीपी में इसका 1.6 फीसदी का योगदान था।

अर्थव्यवस्था को उबारने वाला बजट हो

एसोचैम ने राजनीतिक दलों से यह पक्का करने के लिए कहा कि वित्त वर्ष 2017-19 के केंद्रीय बजट

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर खास रिपोर्ट

अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से उबारने वाला होना चाहिए। आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाना चाहिए, ताकि इस दौर में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। एसोचैम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, 'केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने से सरकार को अपनी पूंजी और अन्य खर्च को अप्रैल से शुरू करने में मदद मिलेगी और आर्थिक विकास की रफ्तार को दोबारा पटरी पर लाने में सहूलियत होगी।' एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, 'नोटबंदी से नकदी का संकट पैदा हुआ है और देश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।'

Dabang Duniya 19 January, 2017

गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति खत्म नहीं हो सकती

ब्लैक मनी से निपटने के लिए स्टॉम्प ड्यूटी में कटौती की सलाह

एजेंसी ✡ नई दिल्ली

उद्योग मंडल एसोचैम ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिए स्टॉम्प शुल्क में कटौती और जमीन-जायदाद का इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है। एसोचैम का मानना है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कालेधन के मौजूदा भंडार को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति का सोना और जमीन-जायदाद जैसे विकल्पों में निवेश को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कालेधन को खत्म करने के लिए नोटबंदी का फैसला जरूरी है। उन्होंने 8 नवंबर को अचानक पुराने नोटों के परिचालन पर रोक लगा दिया था।

उद्योग मंडल की रिपोर्ट जारी

उद्योग मंडल के अध्ययन में बताया गया है कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने से कालेधन के भंडार की समस्या दूर होगी, लेकिन भविष्य में प्रवाह पर इसका असर नहीं होगा। इस तरह के प्रवाह को थामने के लिए संपत्ति के लेन-देन के दौरान लगने वाले स्टॉम्प शुल्क में कमी, जमीन-जायदाद का इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण जैसे उपाय किए जाने की जरूरत होगी।

कर अधिकारियों के पास संसाधन की कमी

अध्ययन के मुताबिक माना जा रहा है कि बैन की गई करेंसी का लगभग पूरा हिस्सा बैंकों में वापस आ चुका है। इससे यह पता चलता है कि बड़े नोटों को चलन से बाहर करने से गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा,'कर अधिकारियों के पास संसाधन संबंधी बाधाओं को देखते हुए इतने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद बनाने की पहचान कठिन कार्य हो सकता है।'